

FORM - II
(For projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Sagar

No. 1456

Dated 11.10.17

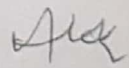
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **21.06 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Baroda Jalasay (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram panchayat Baroda (s) in Sagar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire **21.06 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-6
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Baroda villages (s) is enclosed as Annexure-I to annexure-6
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.


A (A.K. Singh)
Collector
Sagar (M.P.)

बरोदा जलाशय योजना हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही हेतु उपखंडस्तरीय वन अधिकार समिति का प्रस्ताव

दिनांक 21/8/2017 को बरोदा जलाशय हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही हेतु उपखंडस्तरीय वन अधिकार समिति सागर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे—

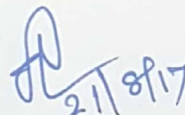
- 1 श्री लक्ष्मीकांत खरे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर
- 2 श्री जी.डी.बरबडे अनुविभागीय अधिकारी (वन) सागर।
- 3 श्री अंकुर शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उपसंभाग क्रमांक 3 गढाकोटा
- 4 श्री के.के.सूर्येश सदस्य सचिव उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति सागर

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन संभाग क्रमांक 3 द्वारा बताया गया कि सागर जिले के सागर विकासखंड के अंतर्गत बरोदा जलाशय हेतु विकासखंड की ग्राम पंचायत बरोदा ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आधार पर 03 वन अधिकार पत्र धारकों के कक्ष क्रमांक पीएफ 814 के अंतर्गत 1 श्री कलू/भगवानदास, 2 श्री फेरन/फूलसींग 3 श्री गनपत/धन्नी गौड के हक प्रभावित हो रहे हैं।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। तदोपरांत बरोदा जलाशय हेतु वन व्यपर्वतन हेतु 03 वन अधिकार पत्र धारक प्रभावित हो रहे हैं जिनके नाम उपर वर्णित हैं अतः उन्हें शासन के नियमानुसार वन अधिकार पत्र धारकों को मुआवजा इत्यादि मुहैया कराये जाने के उपरांत ही, यह समिति वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की अनुशंसा किये जाने का प्रस्ताव पारित करती है।



(अंकुर शर्मा)
एस.डी.ओ जलसंसाधन
उपसंभाग क 3 गढाकोटा



(जी.डी.बरबडे)
अनुविभागीय अधिकारी (वन)
सागर



(के.के.सूर्येश)
सदस्य/सचिव



(लक्ष्मीकांत खरे) 21/8/17
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सागर